

कीमतें और मुद्रास्फीति: नियंत्रण में

मुद्रास्फीति प्रबंधन में महामारी और उसके बाद के भू-राजनैतिक तनावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतियां पेश कीं। महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ते वैश्विक संघर्षों के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने भारत को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में कोर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य कीमतें प्रभावित हुई थीं। इन घटनाओं का निवल प्रभाव वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में उच्च मुद्रास्फीतिक दबाव था। विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई और सरकार द्वारा तैयार की गई सुविचारित व्यापार नीति उपायों, उचित उत्पादन वृद्धि, वित्त वर्ष 24 में कोर मुद्रास्फीति को चार वर्ष के निचले स्तर तक कम करने में सहायक रही। गतिशील स्टॉक प्रबंधन, खुले बाजार के संचालन, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रियायती प्रावधान और व्यापार नीति उपायों सहित उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई से खाद्य मुद्रास्फीति को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। सामान्य मानसून की संभावना और प्रमुख आयातित वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी से भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के लिए दर्शाए गए अच्छे और सीमाबद्ध मुद्रास्फीति अनुमानों को बल मिलता है। इसके अलावा, मध्यावधि से दीर्घावधिक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण का निर्धारण मूल्य निगरानी तंत्रों और बाजार आसूचना के सुदृढीकरण के साथ-साथ दालों और खाद्य तेलों जिसके लिए भारत की आयात निर्भरता काफी हद तक है, जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के संकेन्द्रित प्रयासों द्वारा किया जाएगा।

परिचय

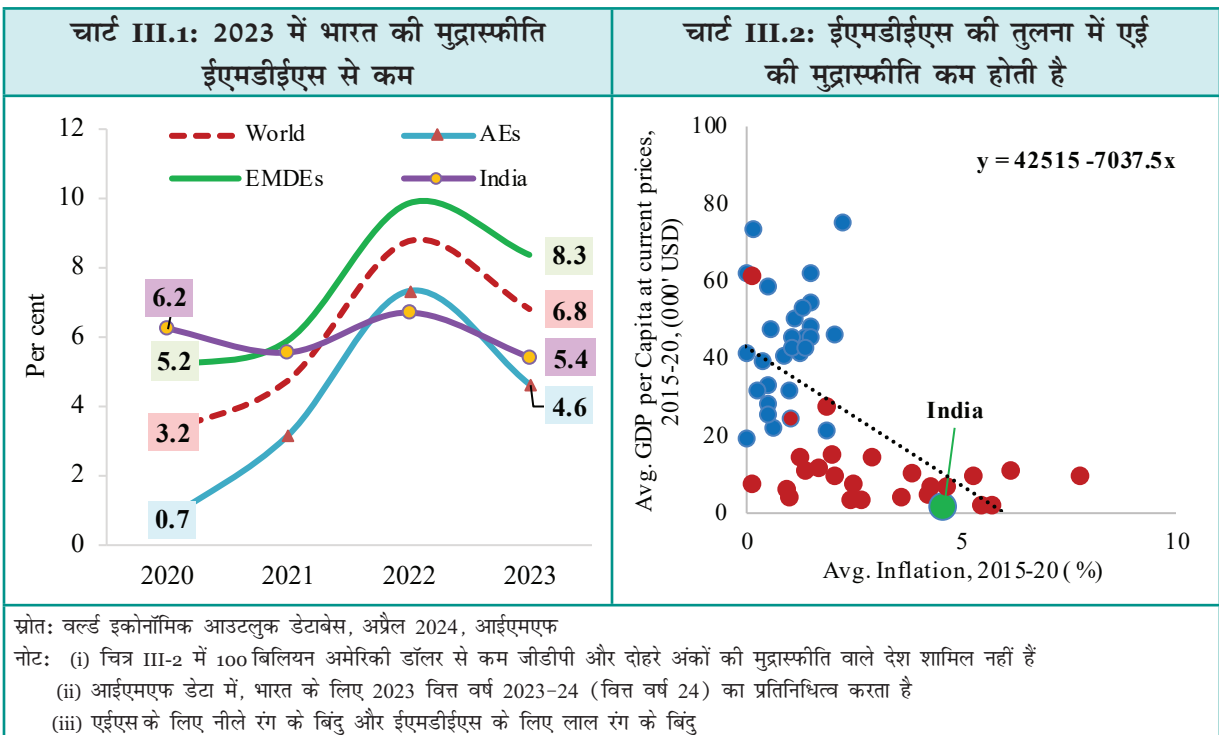
- 3.1. कम और स्थिर मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को मध्यम स्तर पर बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए आर्थिक संकेतकों की सावधानीपूर्वक निगरानी तथा उचित और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा मूल्य स्थिरता और नीतिगत कार्रवाइयों के लक्ष्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की प्रतिबद्धता के साथ, भारत ने वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4 प्रतिशत पर रखने में सफलता प्राप्त की, जो कोविड-19 महामारी अवधि (इसके बाद 'महामारी') के बाद से सबसे निचला स्तर है।
- 3.2. महामारी के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधानों का पुनः सामना किया। वर्ष के उत्तरार्ध और वित्त वर्ष 24 में कीमतों में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से ऊर्जा की कीमतों में, के कम प्रभाव, साथ ही निचले स्तर पर कोर मुद्रास्फीति और मौद्रिक सख्ती के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी आई। आईएमएफ¹ के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित मौद्रिक सख्ती ने इसके उच्च स्तर के तादम्यता और वैश्विक ऊर्जा माँग को कम करने पर परिणामी प्रभाव के कारण ऊर्जा की कीमतों की गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1 विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024, पृष्ठ 3-4 (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024: स्थिर लेकिन धीमा: विचलन के बीच लचीलापन (imf.org))

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति ईएमडीईएस और विश्व औसत से कम है

3.3. मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में लगातार सखी के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में एक अप्रत्याशित लचीलापन देखने को मिला। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईईएस) और उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईएस) दोनों में स्पष्ट है, क्योंकि वे अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों की ओर लौट रहे हैं। यह प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है। आईएमएफ² के आँकड़ों के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति दर वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वैश्विक औसत और ईएमडीईएस की मुद्रास्फीति दर से कम थी।

3.4. अंतर-देशीय मुद्रास्फीति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच एक स्पष्ट नकारात्मक संबंध है। पहले भी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति आम तौर पर ईएमडीईएस की तुलना में कम रही है। स्थापित मौद्रिक नीतियां, आर्थिक स्थिरता, विकसित और कुशल बाजार जैसे कारक जो आपूर्ति और मांग की स्थिति को संतुलित करते हैं, मुद्रास्फीति के प्रभावी प्रबंधन में योगदान करते हैं (हा, कोसे और ओहनसर्ज, 2018)³।

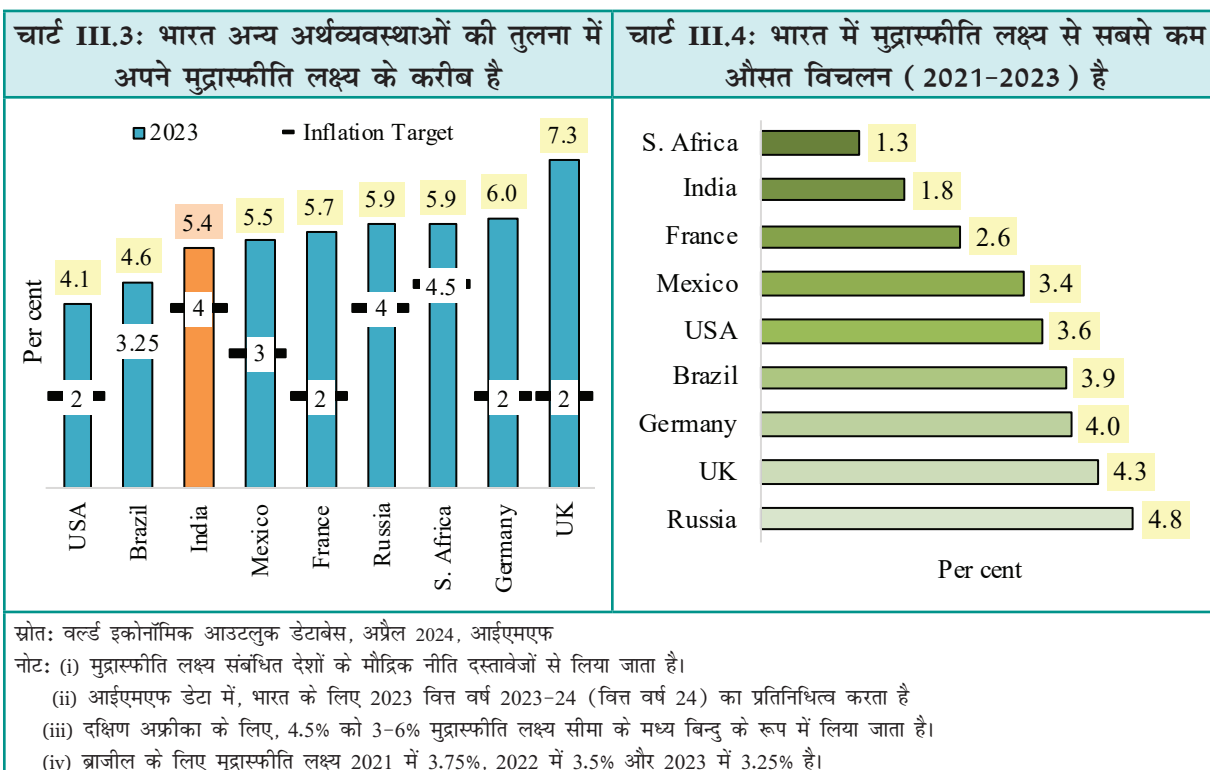


भारत का मुद्रास्फीति प्रबंधन इसे लक्ष्य के भीतर रखने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर था

3.5. मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लक्ष्य के साथ, कई देशों ने विभिन्न कारकों के आधार पर अपने स्वयं के मुद्रास्फीति लक्ष्य स्थापित किए हैं जो उनके आर्थिक उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। आर्थिक विकास का स्तर, अर्थव्यवस्था की संरचना, वित्तीय प्रणाली की स्थिति और मुद्रास्फीति के बीच व्यापार-बंद तथा अन्य आर्थिक उद्देश्यों जैसे कारक इन लक्ष्यों (जहान, सरवत)⁴ को प्रभावित कर सकते हैं। देशों द्वारा निर्धारित विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, वे विभिन्न नीतियों और उपायों को लागू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के संबंध में विभिन्न विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

2 विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024, पृष्ठ 3-4 (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024: स्थिर लेकिन धीमा: विचलन के बीच लचीलापन (imf.org))
 3 हा, जॉर्गीम; कोसे, अयहान; ओहनसर्ज, फ्रांजिस्का लिसेलोटे (2018)। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति: विकास, चालक और नीतियाँ। विश्व बैंक समूह, वाशिंगटन, डी.सी.
 (http://documents.worldbank.org/curated/en/749181542305098752/Inflation-in-Emerging-and-Developing-Economies-Evolution-Drivers-and-Policies)
 4 जहान, सरवत. मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: नियंत्रण बनाए रखना, अर्थशास्त्र को समझना, मूल बातों की ओर वापसी, वित्त एवं विकास, आईएमएफ (मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: नियंत्रण बनाए रखना (imf.org))

3.6. वर्ष 2023 में, भारत की मुद्रास्फीति दर 2 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा के भीतर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में 2021-2023 तक त्रैवार्षिक औसत मुद्रास्फीति में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य से सबसे कम विचलन था। वर्तमान में भू-राजनैतिक तनावों के कारण वैश्विक मांग-आपूर्ति असंतुलन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत की मुद्रास्फीति दर 2023 में वैश्विक औसत से 1.4 प्रतिशत अंक कम थी। इस पृष्ठभूमि में सर्वेक्षण में खुदरा मुद्रास्फीति के रुझानों और अभियानों और उसके घटकों - हेडलाइन, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति में राज्यवार भिन्नता, ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में अंतर और अध्याय में आगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए राजकोषीय नीति संबंधी उपायों पर चर्चा की गई है।

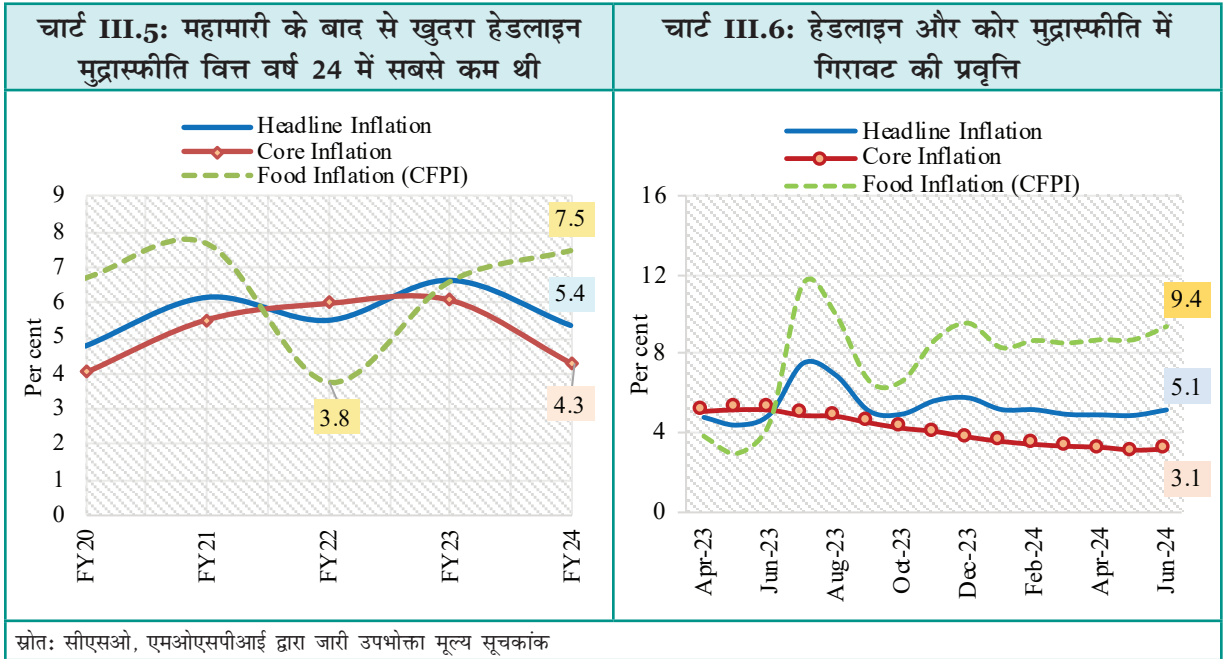


घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति

वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति धीरे-धीरे सामान्य हुई

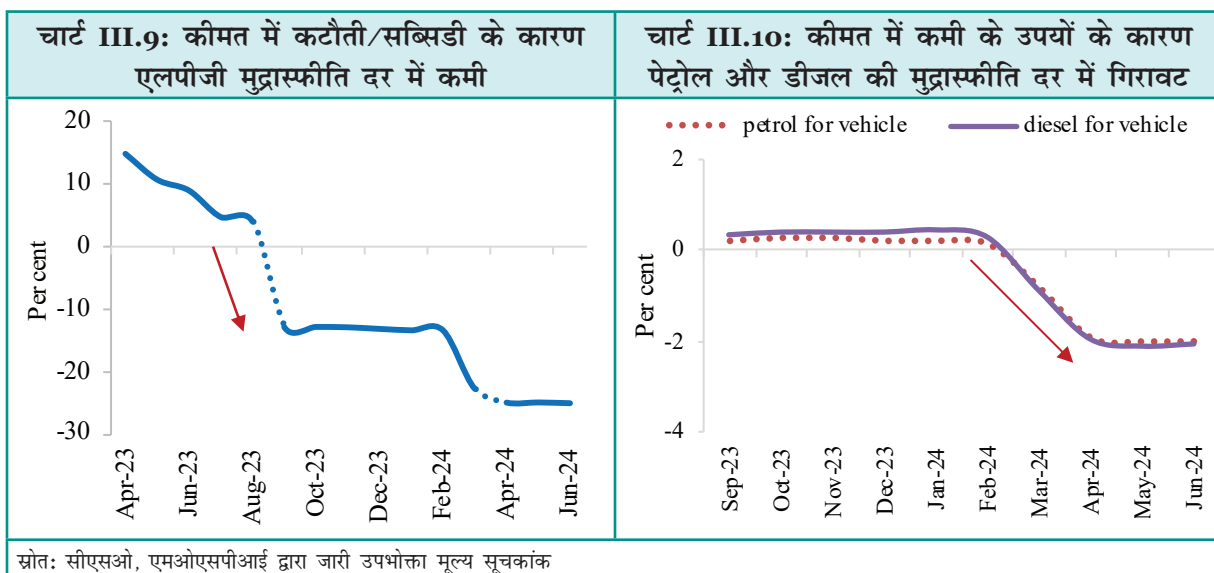
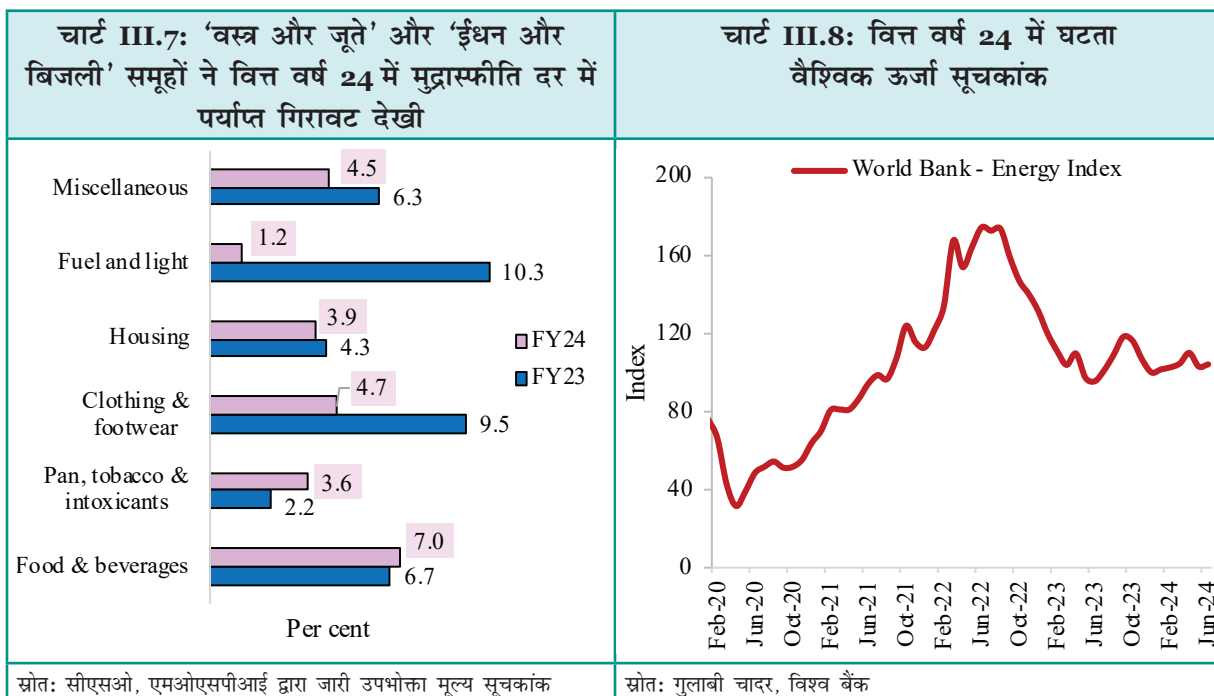
3.7. वर्ष 2020 से, देशों को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त वर्ष 23 में, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से प्रभावित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति मध्यम रही। बाहरी रूप से, रूस-यूक्रेन युद्ध ने, जबकि घरेलू स्तर पर, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला।

3.8. हालांकि, मई 2022 से व्यापक रूप से, मौद्रिक नीति के अन्तर्गत रेपो दर को मई 2022 में 4 प्रतिशत से 250 आधार अंको की वृद्धि करके फरवरी 2023 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाकर प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके बाद, विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से समायोजन की क्रमिक निवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके नीति दर को अपरिवर्तित रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 23 में देखी गई लगातार और स्थिर कोर मुद्रास्फीति जून 2024 में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई।



3.9. चूंकि वैश्विक ऊर्जा मूल्य सूचकांक में वित्त वर्ष 24 में तीव्र गिरावट आयी, जिससे खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति भी कम रही। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के लिए मूल्य कटौती की घोषणा से एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पाद मुद्रास्फीति में कमी आयी। अगस्त 2023 में, देश भर के सभी बाजारों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹200 प्रति सिलेंडर कम कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, एलपीजी मुद्रास्फीति दर सितंबर 2023 से डिफ्लेशन जोन में रही है। मार्च 2024 में, गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर ₹100 की कमी पुनः एक बार की गई थी। इसी तरह मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कमी की। बाद में, वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में डिफ्लेशन जोन में चली गई। इसके अतिरिक्त, 2023 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में गिरावट आयी, जिससे आयातित मुद्रास्फीति चैनल के माध्यम से ऊर्जा, धातुओं, खनिजों और कृषि वस्तुओं में मूल्य दबाव कम हो गया। कम ईंधन और कोर मुद्रास्फीति ने वित्त वर्ष 24 में खाद्य कीमतों में अस्थिरता के बावजूद, हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट सुनिश्चित किया।

3.10. इस प्रकार, मुद्रास्फीति में नरमी काफी हद तक महामारी के बाद के आर्थिक सुधार चरण के दौरान लागू किए गए, विवेकपूर्ण प्रशासनिक उपायों और मौद्रिक नीतियों का परिणाम थी। एमओएसपीआई द्वारा जारी हालिया आकड़ों के अनुसार, जून 2024 में, खुदरा मुद्रास्फीति की दर 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित भाग कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में विस्तृत प्रवृत्तियों और रूपों की जांच करता है।

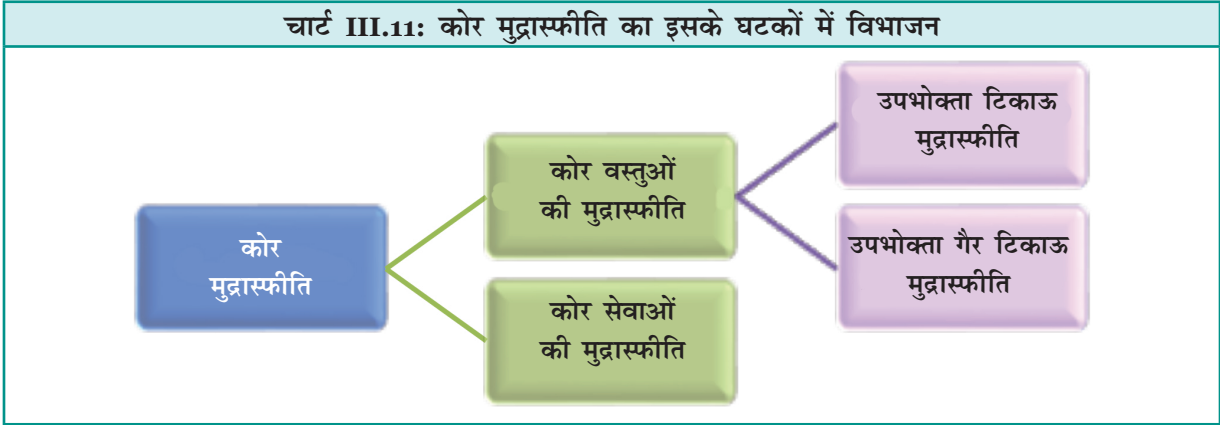


महामारी के बाद की दुनिया में कोर मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

वित्त वर्ष 24 में कोर मुद्रास्फीति चार साल के निचले स्तर पर रही

3.11. कोर मुद्रास्फीति को सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को पृथक करके मापा जाता है। यह अस्थायी आपूर्ति व्यवधानों से उत्पन्न कीमत उतार-चढ़ाव के प्रभाव को व्यापक रूप से समाप्त करके अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित चर्चा कोर मुद्रास्फीति को इसकी वस्तु और सेवाओं घटकों में विभाजित करती है। कोर वस्तुओं को आगे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में विभाजित किया जाता है। कोर वस्तुओं और सेवाओं के सूचकांकों को अलग करने के लिए अपनाई गई विधि अनुलग्नक-1 में दी गई है। इसके घटकों में कोर मुद्रास्फीति का ब्यौरा चार्ट III.11 में दिया गया है।

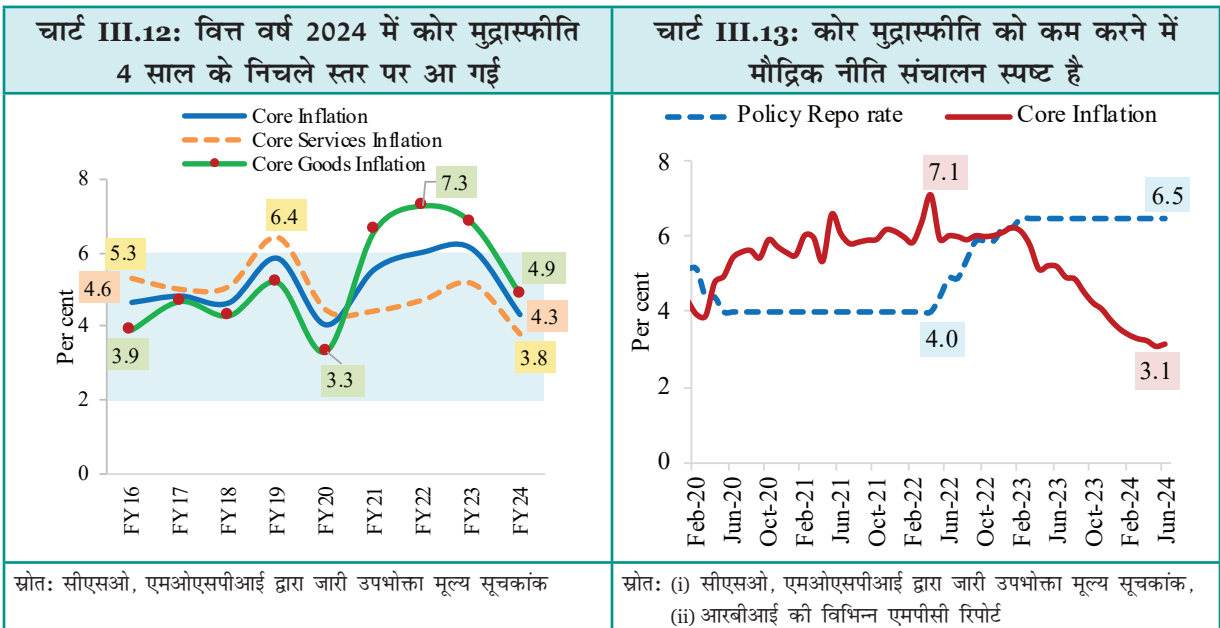
चार्ट III.11: कोर मुद्रास्फीति का इसके घटकों में विभाजन



3.12. महामारी के बाद से, उच्च स्तर के खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण भारत में मुद्रास्फीतिक दबाव वित्त वर्ष 22 में कम हो गया। तथापि, कोर मुद्रास्फीति उसी समय 6 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से प्रभावित थी। जैसा कि चार्ट III.12 में दर्शाया गया है, वर्ष में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन यह बढ़त कोर उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में कम थी।

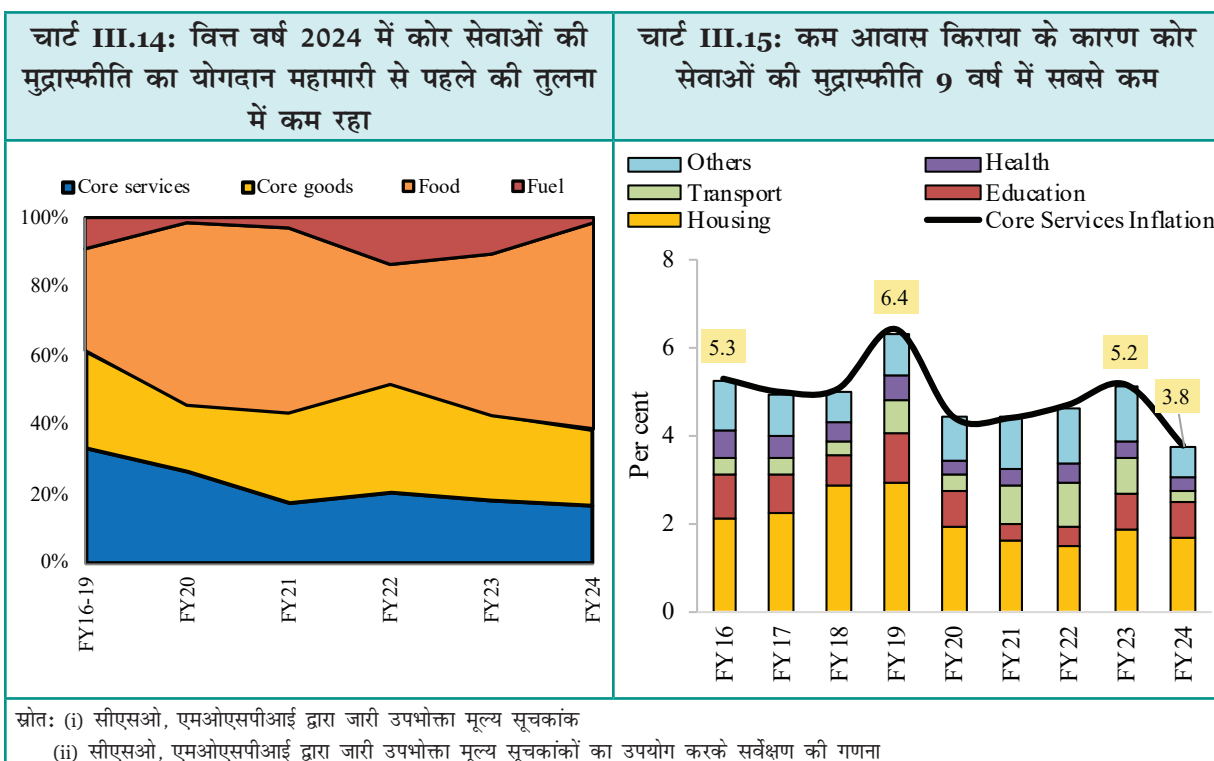
3.13. वित्त वर्ष 23 में मुद्रास्फीतिक संबंधी दबाव फिर से रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित होकर बढ़ गया, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं और खाद्य व ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई। जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधि में तेजी आयी, कोर मुद्रास्फीति में भी थोड़ी वृद्धि हुई और यह मुख्य रूप से कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति से प्रभावित हुई क्योंकि लोगों के शहरी क्षेत्रों में लौटने के साथ घर के किराए में वृद्धि हुई (चार्ट III.15)। वित्त वर्ष 24 में, कीमतों में सुधार हुआ। कोर मुद्रास्फीति - वस्तु और सेवा दोनों में कमी के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी आयी। वित्त वर्ष 24 में कोर सेवा मुद्रास्फीति नौ साल के निचले स्तर पर आ गई; वहीं, कोर वस्तु मुद्रास्फीति भी घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई।

3.14. मौद्रिक नीति की रूपरेखा निर्धारित करने में कोर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं। मूल्य दबावों के उभरते स्वरूपों का आकलन करते हुए, RBI ने मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए मई 2022 से पुनः रेपो दर में धीरे-धीरे 250 आधार अंकों की वृद्धि की। चार्ट III.13 कोरक मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति संचालन के प्रभाव को इंगित करता है, जिसमें अप्रैल 2022 और जून 2024 के बीच 4 प्रतिशत के आसपास की गिरावट आयी है।



सेवा कीमतों में भारी गिरावट ने कोर मुद्रास्फीति में कमी को बढ़ावा दिया है

3.15. कोर सेवाओं की स्थिर कीमतें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (बॉक्स III.1) के मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण के लिए एक जोखिम कारक हैं। इसके विपरीत, भारत की कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में नौ वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके लिए 2023⁵ में नए घरों के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ आवास किराये संबंधी मुद्रास्फीति में नरमी भी जिम्मेदार थी।



बॉक्स III.1: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति के लिए अत्यधिक जोखिम

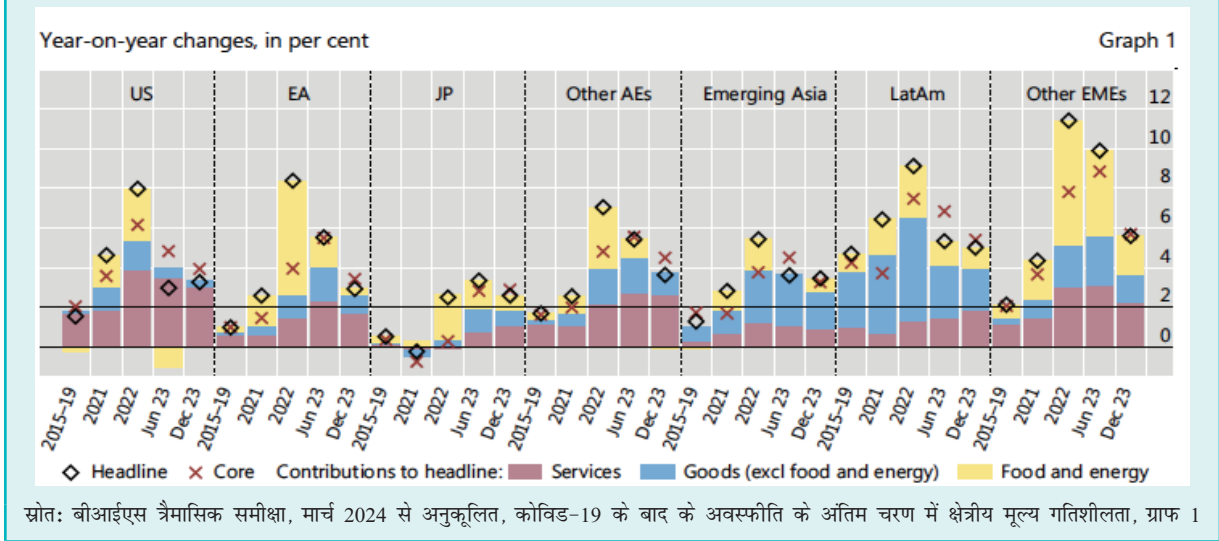
बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स⁶ की मार्च 2024 की त्रैमासिक समीक्षा के अनुसार, 2023 में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति अधिक रही। जबकि 2023 में आपूर्ति श्रृंखला के क्रमिक सामान्यीकरण के बाद खाद्य, ऊर्जा और कोर वस्तुओं की कीमतों में स्पष्ट वापसी हुई थी, समीक्षा से यह भी पता चला है कि कोर वस्तुओं की कीमतों में मंदी की हालिया गति पिछले मामलों से निकटता से मेल खाती है, जबकि साथ ही, सेवाओं में मूल्य वृद्धि पिछली मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही है। सेवा मुद्रास्फीति की लगातार प्रकृति सेवाओं में बहुत अधिक श्रम तीव्रता के कारण है। आवास की बढ़ती कीमतों ने भी इसमें योगदान दिया।

ये गतिशीलता विभिन्न देशों और क्षेत्रों में समान रूप से देखी गई है लेकिन उभरती एशियाई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और लैटिन अमेरिका में ऐसा कम है (चार्ट III.16)। आगे बढ़ते हुए, सेवाओं की मुद्रास्फीति में दृढ़ता का उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में एई पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवाएं एई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का एक बड़ा भाग हैं, जो उनके हेडलाइन मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए अधिक जोखिम भरा है।

5 <https://www.proptiger.com/guide/post/new-home-sales-record-33-yoy-growth-in-2023-proptiger-com-report>

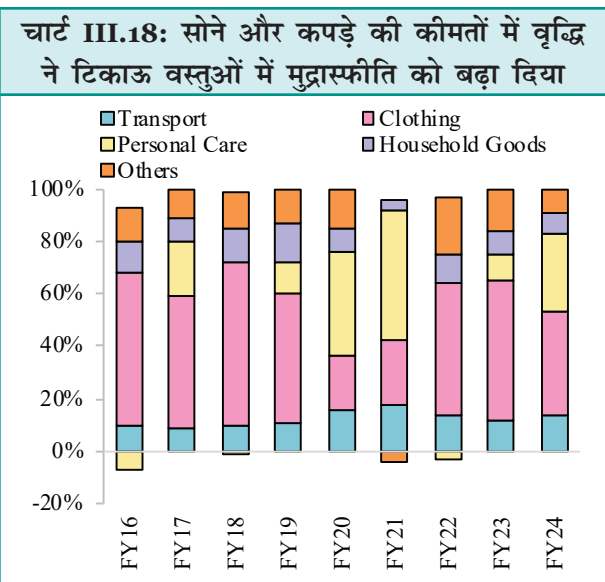
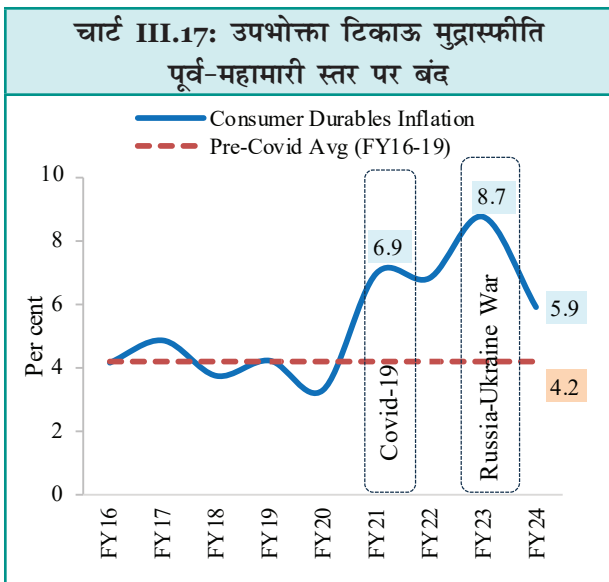
6 बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा, मार्च 2024, कोविड-19 के बाद की मुद्रास्फीति के अंतिम पड़ाव में क्षेत्रीय मूल्य गतिशीलता। (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2403d.htm)

चार्ट III.16: AEs में लगातार कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का जोखिम



उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति में बढ़त बनी रही लेकिन वित्त वर्ष 24 में इसमें गिरावट हुई

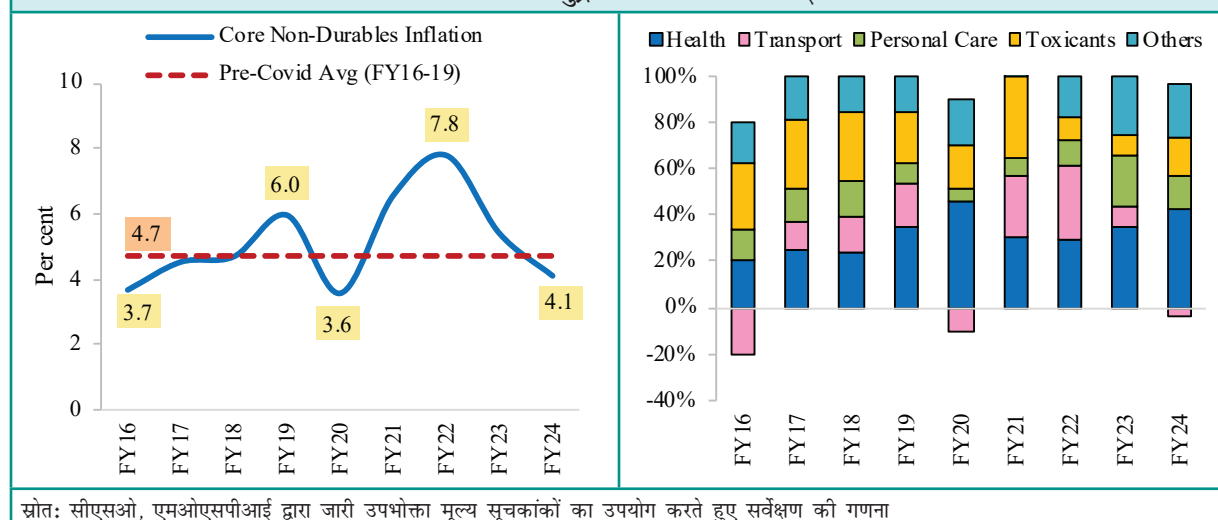
3.16. उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच उत्तरोत्तर 5 प्रतिशत बिन्दु से अधिक बढ़ गया। वित्त वर्ष 21 में सोने की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई, जो सीपीआई की व्यक्तिगत देखभाल श्रेणी का एक प्रमुख घटक है। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में, उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांक में 48 प्रतिशत भाग वाले, कपड़े, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख घटक था। परिधान निर्माताओं, विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री कपास की कीमतों में वृद्धि के कारण यह हुआ। प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार के साथ, वित्त वर्ष 24 में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में गिरावट आयी। हालांकि, फेड दर में कटौती और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने से सोने की रिकॉर्ड उच्च कीमतों ने समग्र टिकाऊ मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डाला है।



कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मुद्रास्फीति में भारी गिरावट

3.17. उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (सीएनडी) के सीपीआई बास्केट में तीन घटक होते हैं - खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन और अन्य उपभोग की वस्तुएं (विवरण अनुलग्नक-1 में)। यह खंड केवल अन्य कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ घटकों (सीएनडी की अन्य उपभोग की वस्तुएं) की जांच करता है। बाद के खंड 'खाद्य और पेय पदार्थ' की जांच करेंगे, जबकि 'ईंधन और बिजली' को पहले ही पैराग्राफ 3.9 में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। जबकि कोर सीएनडी मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 20 में गिर गई, यह वित्त वर्ष 21 में बढ़ना शुरू हुई, वित्त वर्ष 22 में एक सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गई, और वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में तेजी से गिर गई। इसके लिए अंतर्निहित कारण मुख्य रूप से परिवहन घटकों की लागत में परिवर्तन रहा है।

चार्ट III.19: (क) और (ख): परिवहन घटक में गिरावट के कारण कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मुद्रास्फीति में कमी आई

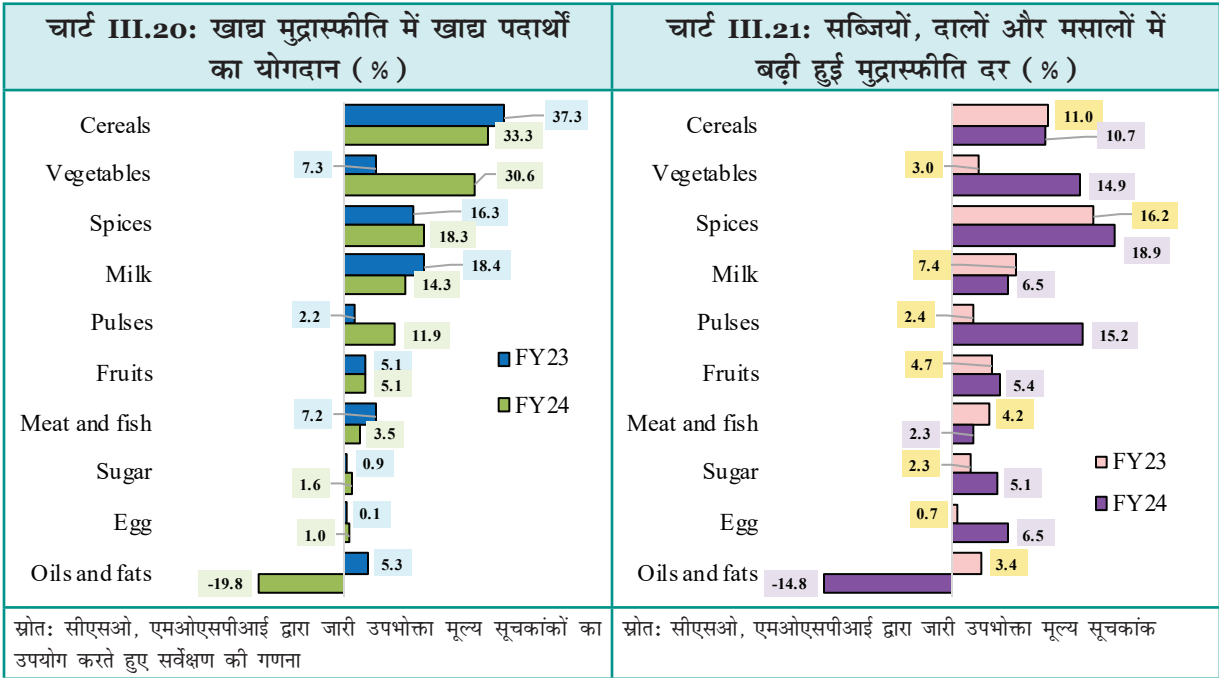


खाद्य मुद्रास्फीति

प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव

3.18. पिछले दो वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना रही है। अनुसंधान⁷ जलवायु परिवर्तन के लिए खाद्य कीमतों की बढ़ती सुभेद्यता को इंगित करता है - गर्म हवाएं, असमान मानसून वितरण, बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, मूसलाधार वर्षा और ऐतिहासिक शुष्क स्थितियां (पात्रा, जॉन एंड जॉर्ज, 2024)। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में, कृषि क्षेत्र प्रतिकूल मौसम, जलाशय के कम स्तर और क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हुआ जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 22 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 6.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 में 7.5 प्रतिशत हो गई।

7 पात्रा, एम.डी., जॉन, जे., और जॉर्ज, ए.टी. (2024)। क्या खाद्य कीमतें भारत की मुद्रास्फीति का 'असली' मूल हैं? आरबीआई बुलेटिन, 78(1): 87-98 (RBIBULLETINJANUARY2024EC59F69FFEA5447B9A75C33E7CA8CB26-PDF)



प्रमुख खाद्य वस्तुओं में कीमत वृद्धि के कारण

3.19. सब्जियों और दालों की उत्पादन संभावनाएं विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित हुईं। जुलाई 2023 में टमाटर की कीमतों में वृद्धि फसल उत्पादन में मौसमी बदलाव, वाइट फ्लाइ के संक्रमण जैसी क्षेत्र-विशिष्ट फसल रोगों और देश के उत्तरी भाग में मानसून के जल्दी आगमन के कारण हुई थी। भारी बारिश के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में रसद सेवाओं में भी व्यवधान आया। प्याज की कीमतों में तेजी कई कारकों के कारण आयी है, जिसमें पिछले कटाई सत्र के दौरान बारिश का रबी प्याज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव होना, खरीफ सत्र के दौरान बुवाई में देरी, लंबे समय तक सूखे की अवधि से खरीफ उत्पादन प्रभावित होना और अन्य देशों द्वारा किए गए व्यापार संबंधी उपाय शामिल हैं।

3.20. दालों, विशेष रूप से तुअर की कीमतों में वृद्धि पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण कम उत्पादन की वजह से हुई है। रबी सीजन में धीमी बुवाई और दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी परिवर्तन के कारण उड़द का उत्पादन प्रभावित हुआ था। पिछले रबी सीजन की तुलना में चने का क्षेत्र और उत्पादन भी कम रहा।

3.21. वर्ष 2023 की शुरुआत से दूध की कीमत में बढ़ोतरी रही है। यह महामारी के चरम दिनों के दौरान कृत्रिम गर्भाधान में कमी के साथ-साथ पशु आहार की उच्च लागत के कारण हुआ था है। दूध सहकारी समितियों ने बढ़ी हुई लागत के कारण दूध और दूध उत्पादों की कीमत में वृद्धि की। दूध की कीमत में वृद्धि वित्त वर्ष 24 के अंत तक कम हो गई।

3.22. हालांकि, सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री, निर्दिष्ट दुकानों में खुदरा बिक्री और समय पर आयात सहित त्वरित कार्रवाई की (बॉक्स III.2)। इसके अतिरिक्त, गरीबों हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, को जनवरी 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

बॉक्स III.2: वित्त वर्ष 24 में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक उपाय**गेहूं/आटा**

- गेहूं के आटे, मैदा और सूजी के निर्यात को अगस्त 2022 से निषिद्ध श्रेणी में रखा गया था।
- जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए, जून 2023 से मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाई गई थी।
- नवंबर 2023 में, सरकार ने उपभोक्ताओं हेतु इसे किफायती बनाने के लिए ₹27.50 प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा की शुरूआत की।
- खुले बाजार में बिक्री के लिए केन्द्रीय पूल से समय-समय पर गेहूं और चावल को निकाला जाता है।

चावल/धान

- सरकार ने क्रमशः सितंबर 2022 और जुलाई 2023 में टूटे चावल और गैर-बासमती चावल के निर्यात को निषिद्ध श्रेणी के तहत रखा।
- बासमती चावल की आड़ में होने वाले गैर-बासमती चावल के निर्यात को रोकने के लिए, बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य अक्टूबर 2023 में तय किया गया था।
- पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, सरकार ने 31 मार्च 2024 तक पारसेला चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया।
- फरवरी 2024 में, सरकार ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी शृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर/मिलरों द्वारा चावल/धान के स्टॉक की स्थिति घोषित करने के लिए अनिवार्य किया।
- फरवरी 2024 में, सरकार ने एनएएफईडी, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से ₹29 प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत चावल बेचना शुरू किया।

दालें

- उपभोक्ताओं को उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए दालों के बफर स्टॉक से पर्याप्त सूझबूझ से रिलीज की जा रही है।
- घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और दालों की कीमतों को कम करने के लिए, अरहर और उड़द के आयात को 31 मार्च, 2025 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखा गया है। मसूर पर मूल आयात शुल्क 31 मार्च, 2024 तक घटाकर शून्य कर दिया गया था।
- सरकार ने अत्यधिक रियायती दर पर खुदरा निपटान के लिये चना स्टॉक को चना दाल में बदलने के लिये जुलाई 2023 में भारत दाल की शुरूआत की। बाद में, भारत दाल को मूंग दाल और मूंग साबूत को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।
- इसके अलावा, भारत ने वित्त वर्ष 24 में काफी मात्रा में अरहर (मुख्य रूप से मोजाम्बिक, म्यांमार, तंजानिया, सूडान और मलावी से), मसूर (मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस से) और उड़द (मुख्य रूप से म्यांमार से) आयात किया।

प्याज

- पीएसएफ के तहत प्याज बफर वित्त वर्ष 21 में 1.00 एलएमटी से बढ़ाकर वित्त वर्ष 24 में 7.00 एलएमटी कर दिया गया था। यह स्टॉक खुदरा बिक्री, ई-नाम नीलामी और थोक बाजारों में थोक बिक्री के माध्यम से जारी किया गया था।
- सरकार ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक प्याज की विशिष्ट किस्मों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य रखा।
- दिसंबर 2023 में, प्याज की निर्यात नीति को 31 मार्च, 2024 तक 'मुक्त' से 'निषिद्ध' श्रेणी में संशोधित किया गया था।

खाद्य तेल

- कच्चे पाम तेल, कच्चा सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। तेल पर कृषि उपकर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। जनवरी 2024 में, इस शुल्क संरचना को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
- रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर घटी बेसिक ड्यूटी स्ट्रक्चर को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- रिफाइंड पाम तेलों के मुक्त आयात को अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया था।

चीनी

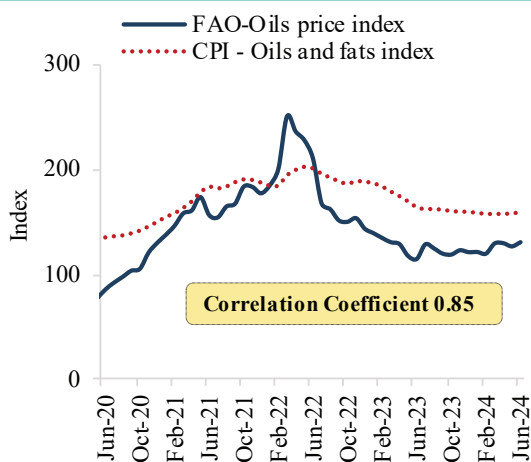
- अक्टूबर 2023 में, सरकार ने चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंधों की तारीख को 31 अक्टूबर, 2023 से आगे अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

वैश्विक खाद्य कीमतें और घरेलू मुद्रास्फीति

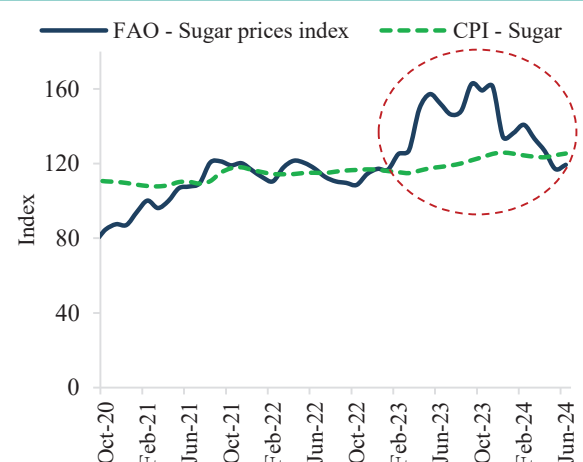
3.23. भारत में, खाद्य तेल बाजार बहुत हद तक आयात पर निर्भर करता है, जिसमें कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 50 प्रतिशत से अधिक आयात⁸ किया जाता है, जिससे यह वैश्विक कीमतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य तेल मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव इन वैश्विक मूल्य रुझानों का एक प्रमुख संकेतक है। इस सूचकांक में हाल की गिरावट की प्रवृत्ति मोटे तौर पर भारत में घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के साथ सहसंबद्ध है। इसके परिणामस्वरूप सरकार उपभोक्ताओं के लिए रियायती दर पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों की गहन निगरानी करती है। वैश्विक मूल्य अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आयातों को घरेलू उत्पादन के साथ संतुलित करने के प्रयास भी किए जाते हैं। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम का उद्देश्य आयात बोझ को कम करने के लिए घरेलू कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ाना है।

3.24. चीनी के मामले में, सरकार ने जून 2022 में निर्यात पर प्रतिबंधों की घोषणा की ताकि पर्याप्त स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इस प्रकार चीनी मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जा सके। इन निर्यात प्रतिबंधों ने वास्तव में घरेलू चीनी की कीमतों को स्थिर करने में भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप, भले ही वैश्विक चीनी मूल्य सूचकांक बढ़ गया है और फरवरी 2023 से अस्थिरता दिख रहा है, किंतु घरेलू चीनी की कीमतें बहुत कम अस्थिर रही हैं।

चार्ट III.22: वैश्विक और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों का सह-संचलन



चार्ट III.23: चीनी पर निर्यात प्रतिबंध से भारत में चीनी की कीमतें स्थिर हो गईं



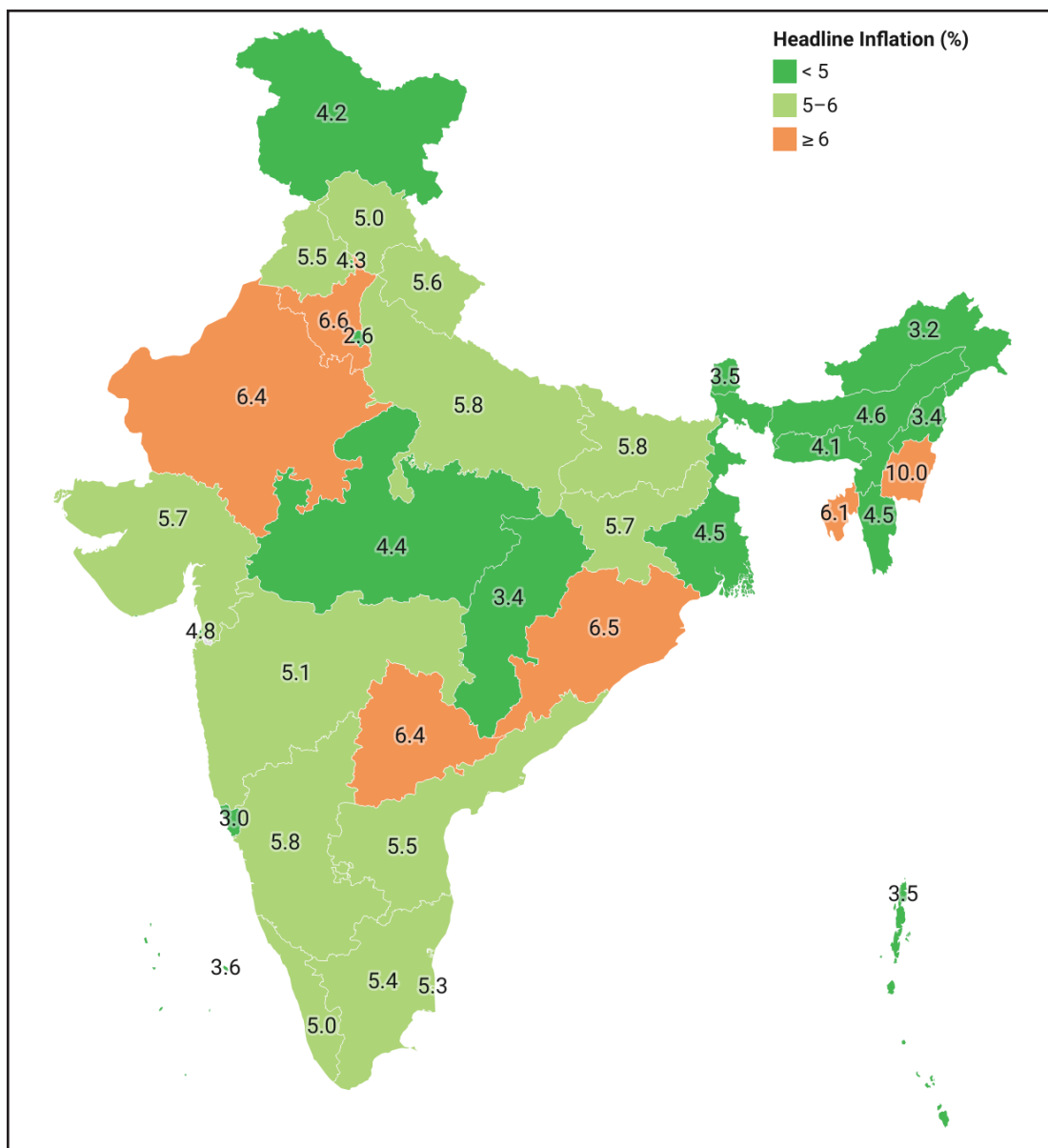
स्रोत: (i) CSO, MoSPI द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ii) FAO द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक डेटा

8 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दिनांक 14 मार्च 2024 की पीआईबी विज्ञप्ति। (pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2014554)

खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय अंतर

3.25. वित्त वर्ष 24 में अखिल भारतीय औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर में गिरावट के अनुरूप, अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में गिरावट आयी। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 29 में मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत से कम थी।

चार्ट III.24: वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति (%) में अंतरराज्यीय बदलाव

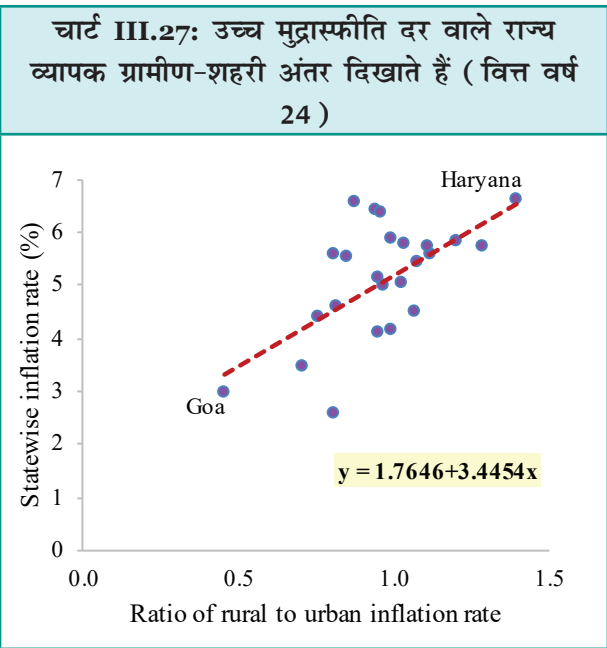
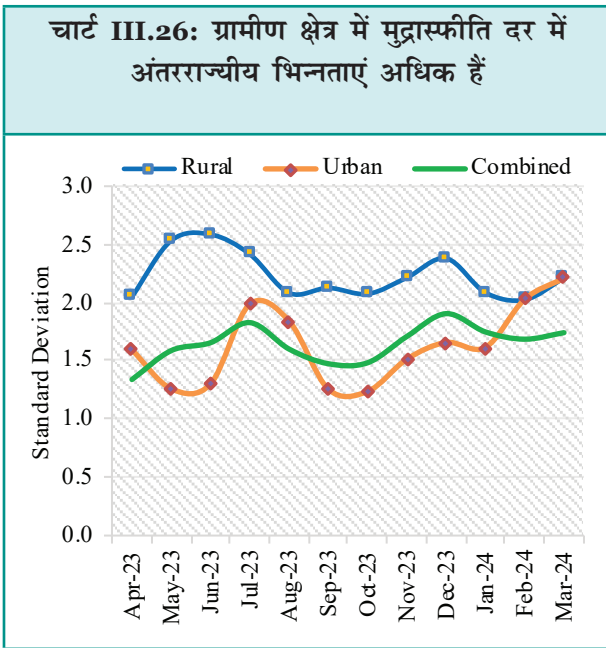
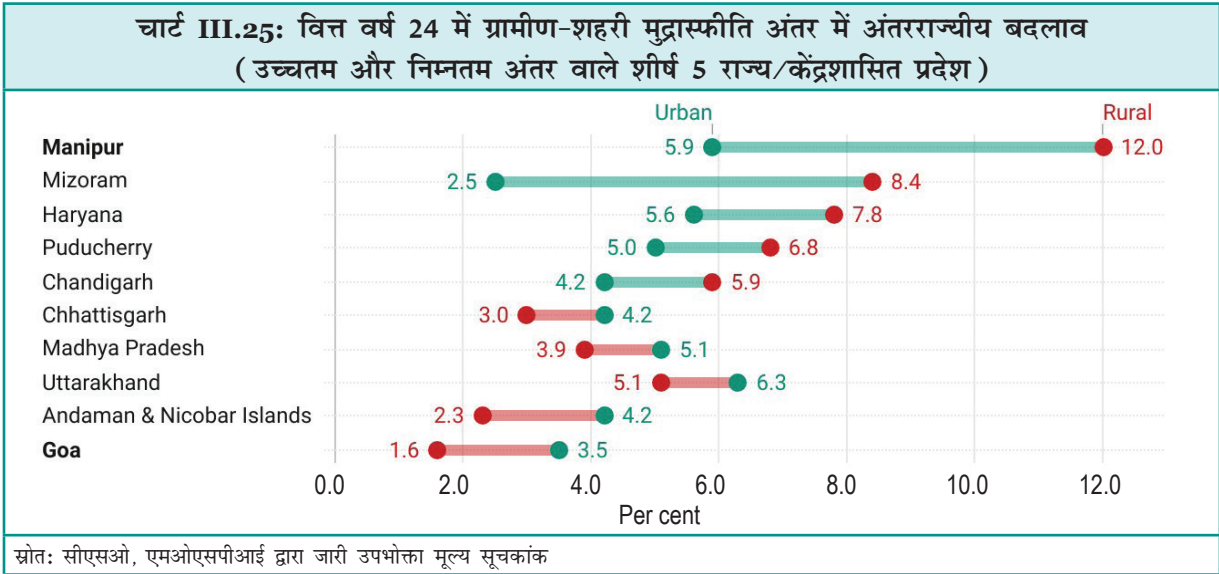


स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से तैयार

ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय अंतर अधिक स्पष्ट हैं

3.26. उपभोग बास्केट में शहरी (29.6%) की तुलना में ग्रामीण खाद्य पदार्थों का बहुत अधिक भार (47.3%) है। इसलिए, पिछले दो वर्षों में, जिन राज्यों में खाद्य कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने भी उच्च ग्रामीण मुद्रास्फीति का अनुभव किया। यह भी पाया गया है कि मानक विचलन के माध्यम से परिकल्पित अंतर-राज्यीय भिन्नता शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण में अधिक है। इसके अलावा, उच्च समग्र मुद्रास्फीति वाले राज्यों में भी ग्रामीण से शहरी मुद्रास्फीति का व्यापक अंतर प्रदर्शित होता है और ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक है। विभिन्न राज्यों के लिए उनके

ग्रामीण-से-शहरी मुद्रास्फीति अनुपात की तुलना में समग्र मुद्रास्फीति का बिखराव एक सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच का अंतर गोवा की तुलना में बहुत व्यापक था, जिसमें अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति थी।



स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
नोट: स्कैटर प्लॉट 23 प्रमुख राज्यों और दिल्ली के एनसीटी के उप-नमूने पर आधारित है

दृष्टिकोण और समाधान

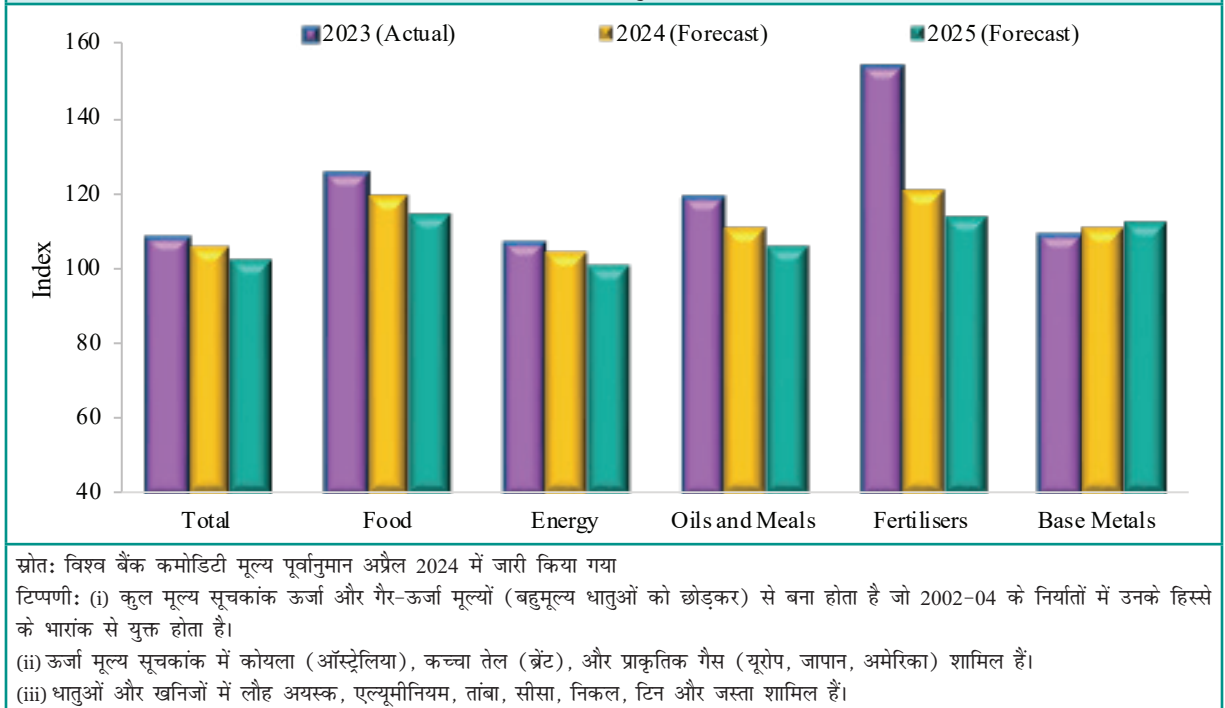
3.27. आरबीआई और आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर सरेखित होगी। सामान्य मानसून और आगे कोई बाहरी या नीतिगत बदलाव नहीं मानते हुए, आरबीआई⁹ को उम्मीद है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 में 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 में 4.1 प्रतिशत

9 मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2024, पृष्ठ 7 (MPRAPRIL2024866555514098406BA610767D0E792E87.PDF (rbi.org.in))

होगी। आईएमएफ¹⁰ ने भारत के लिए 2024 में 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है।

3.28. विश्व बैंक¹¹ को उम्मीद है कि वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि होगी, और इसलिए बेहतर औद्योगिक गतिविधि और व्यापार वृद्धि के कारण उनकी मांग बढ़ेगी। इसे 2024 में वस्तु मूल्य सूचकांक में 3 प्रतिशत की कमी और 2025 में 4 प्रतिशत की कमी का अनुमान है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक की कम कीमतों से प्रेरित है। इस वर्ष कोयले और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के कारण ऊर्जा मूल्य सूचकांक में गिरावट की उम्मीद है। उर्वरक की कीमतों में कमी होने की संभावना है, लेकिन ये मजबूत मांग और निर्यात प्रतिबंधों के कारण 2015-2019 के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। मूल धातु की कीमतों में वृद्धि का अनुमान है, जो वैश्विक औद्योगिक गतिविधि और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है। सामान्यतः भारत द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्यों में मौजूदा अधोमुखी उतार-चढ़ाव घरेलू मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए सकारात्मक है।

चार्ट III.28: 2025 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में प्रत्याशित गिरावट



3.29. कुल मिलाकर भारत के लिए अल्पकालिक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण सामान्य है। हालांकि, दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित विकल्पों का पता लगाया जा सकता है।

- खाद्य तेलों की घरेलू खपत उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। इस स्वरूप को उलटने और घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए, सूरजमुखी तथा रेपसीड और सरसों जैसे प्रमुख तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयास करना और राइस ब्रान तेल और मकई के तेल जैसे गैर-पारंपरिक तेलों के महत्व का पता लगाना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के दायरे को ताड़ के तेल के अलावा अन्य प्रमुख तिलहनों तक बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।
- भारत दालों में लगातार कमी और इसके परिणामस्वरूप कीमत दबावों का सामना कर रहा है। दालों का उत्पादन देश के कुछ राज्यों और जिलों में केंद्रित है और जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति संवेदनशील है। अधिक जिलों और चावल परती क्षेत्रों में दलहनों, विशेष रूप से मसूर, अरहर और उड़द के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और

10 विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024, पृष्ठ 36 (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024: स्थिर लेकिन धीमा: विचलन के बीच लचीलापन (imf.org))

11 विश्व बैंक की अप्रैल 2024 की क्मोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट (क्मोडिटी मार्केट्स आउटलुक (अप्रैल 2024) (worldbank.org))

अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में उड़द और मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती को बढ़ावा देने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- सब्जियों के लिए भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों के मूल्यों में लगातार मौसमी उछाल को ध्यान में रखते हुए, ऐसी विशिष्ट फसलों के लिए अनुकूल आधुनिक भंडारण सुविधाओं को विकसित करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना और ऐसी सुविधाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है जिनकी सेवाओं की अत्यधिक मौसमी मांग है।
- वित्त वर्ष 24 में विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए सरकार द्वारा तेज और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। यह 500 से अधिक केंद्रों पर कीमतों की दैनिक निगरानी पर आधारित था। संभावित रूप से, एक महत्वपूर्ण कारक जो इस तरह की कार्रवाई की तेजी और प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है, वह कीमतों और उनके सूचकांकों पर पूर्ण स्पष्टता है। इस मोर्चे पर, निम्नलिखित क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई को ठीक करना और तेज करना महत्वपूर्ण हो सकता है।
 - विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र किए गए आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए उच्च आवृत्ति मूल्य निगरानी आंकड़ों को इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रत्येक चरण में कीमतों का निर्धारण मात्रात्मक और निगरानी योग्य हो।
 - वस्तुओं और सेवाओं हेतु उत्पादक मूल्य सूचकांक बनाने के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लायी जा सकती है, ताकि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के प्रकरणों को बेहतर समझा जा सके। इसके अलावा, इस बात को ध्यान में रखते हुए एमओएसपीआई के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, 2022-23 के परिणाम उपलब्ध हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नए भार और आइटम बास्केट के साथ शीघ्रता से संशोधित करना उचित होगा।

अनुलग्नक 1: कोर मुद्रास्फीति के घटकों के लिए व्युत्पन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का समूह और उनके वजन

	कोर सेवाएँ		कोर वस्तुएँ		कोर वस्तुएँ			
	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन	कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ		कोर उपभोक्ता टिकाऊ	
प्रमुख समूह/उप-समूह	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन
पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	–	–	16	2.4	16	2.4	–	–
कपड़े और जूते	2	0.5	25	6.0	–	–	25	6.0
घरेलू सामान और सेवाएँ	4	0.9	44	2.9	8	1.7	36	1.2
स्वास्थ्य	4	1.8	3	4.1	2	4.0	1	0.1
परिवहन और संचार	13	4.6	8	4.0	3	2.4	5	1.6
रिक्रिएशन और मनोरंजन	8	1.1	9	0.6	1	0.2	8	0.4
शिक्षा	3	3.5	2	1.0	2	1.0	–	–
व्यक्तिगत देखभाल और उससे संबंधित वस्तुएँ	1	0.6	15	3.3	7	2.1	8	1.3
आवास	10	10.1	–	–	–	–	–	–
कुल	45	23.0	122	24.3	39	13.7	83	10.6
<p>स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से गणना की जाती है</p> <p>नोट: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुख्य वस्तुओं और सेवाओं का कुल भार 47.3 प्रतिशत है, जो मुख्य वस्तुओं और मुख्य सेवाओं का कुल भारांश है। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के कुल भार का योग मुख्य वस्तुओं के कुल भारों में होता है।</p>								

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है